काण्डला बन्दरगाह पर तेल उतारने की सुविधा

*67. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि काण्डला बन्दरगाह पर विदेश से आयात किये तेल को उतारने की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है,

(ख) यदि हां, तो इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं, और

(ग) क्या केवल तेल उतारने के लिए एक गोदी का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है ?

THE MINISTER OF SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI VEERENDRA PATIL): (a) to (c). There are two oil jetties at Kandla Port exclusively meant for handling liquid cargoes like POL, edible oils and chemicals. In addition, edible oil vessels can also be handled at one of the general cargo berths. A proposal for replacement of one of the oil jetties, which has outlived its life, has been sanctioned and the contract for construction of the new jetty awarded. With the construction of the new jetty, certain constraints in the berthing of tankers would be removed. Presently, the existing facilities are somewhat inadequate; the position is, however, expected to ease with the commissioning of the Mathura Oil Refinery.

श्री नरसिंह मकवाना : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दोनों जट्टियां पुरानी हैं, दोनों पर काम नहीं होता है । तो एक जेटी के लिये रुपया दिया गया है लेकिन दूसरी के लिये क्यों नहीं दिया गया है ? और टैंकरों पर जो पाबन्दी तेल ले जाने की लगायी है वह कौन सी तारीख से लगायी है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : दोनों जट्टियां पुरानी नहीं हैं । एक जेटी पुरानी है और दूसरी जेटी 1955 में बनायी गयी है । 1955 या 1957 में बनी है, मुझे ठीक तौर से याद नहीं है । लेकिन दोनों जट्टियों की कैपेसिटी 30 लाख टन हैंडिल करने की है । इसलिये जितना आयल, लिक्विड कार्गो आता है वह पूरा हैंडिल करने की कैपेसिटी है अब लेकिन एक जेटी जो 1930 में बनी हुई थी वह बहुत पुरानी हो गई है इसलिये उसको बदल कर और एक जेटी बनाने के लिए हमने मंजूरी दे दी है । 6 करोड़ रुपये से ऊपर उस पर खर्च किया जाता है । कंट्रेक्ट भी हमने दे दिया है और वह जेट्टी, मैं समझता हूं कि 18,20 महीने में तैयार हो जायेगी । उसके तैयार होने के बाद जो भी मसायल हैं, वह सब सुलझ जायेंगे ।

श्री नरसिंह मकवाना : मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, उनका कहना है कि एक जेट्टी काम नहीं दे सकती है और दूसरी कंट्रेक्ट देकर नई बनवायेंगे, मगर दोनों में से किसी पर काम नहीं चलता है, उसकी क्या वजह है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैंने साफ तौर से कहा है कि दोनों जेट्टी काम कर रही हैं और मेरे पास फिगर्स हैं । दोनों आयल जेट्टियों की कैपेसिटी 1978–79 में 30 लाख टन है ।

अध्यक्ष महोदय : हम आपत्ति उठा सकते हैं, इस पर ।

In 1978-79, the capacity was 30 lakh tonnes. But actually handled was 29.26 lakh tonnes and the utilisation was 97.53 per cent. In 1979-80, the capacity was 30 lakh tonnes, actually handled was 25.39 lakhs tonnes and the utilisation was 84.63 per cent in 1980-81, the capacity was again 30 lakh tonnes, actually handled was 32.14 lakh tonnes and the utilisation was 107.13 per cent.

कैपेसिटी जितनी है, उससे भी ज्यादा आयल आ रहा है, उसको भी हम हैंडिल कर रहे है ।

आचार्य भगवान देव : दुर्भाग्यवश कराची बन्दरगाह जब हमारे हाथ से चला गया तो कांडला बंदरगाह को डैवलप किया गया, रेलवे लाइन भी वहां पर बिछाई, पहले मीटर गेज थी उसे ब्राड गेज किया । क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि यात्री जहाजों को वहां तक ले जाने के लिये कोई योजना है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : कांडला तक पैसेन्जर्स शिप ले जाने के बारे में हमारे सामने कोई प्रपोजल नहीं है । अगर मुगल लाइन्स से कोई प्रपोजल आया तो देखेंगे, लेकिन एक प्रपोजल है मुगल लाइन्स लिमिटेड का, जो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनी है, वह रोरो शिप मंगलौर से जाफराबाद तक चलाना चाहते हैं। एक माननीय सदस्य ने मुझसे कहा कि जाफराबाद तक नही कांडला तक वह जाना चाहिए । मैंने कहा कि प्रपोजल आने दीजिये, तब उस पर विचार करेंगे ।

श्री दया राम शाक्य : मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में कहा है कि कांडला बन्दरगाह में दो जैट्टी का काम ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है और मथुरा रिफाईनरी में काम पूर्ण होने पर वहां का कारोबार बिल्कुल उत्तम हो जायेगा और उससे सुविधा होगी । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, यद्यपि उसका सीधा संबंध नहीं है, परन्तु मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है, इसलिये पूछ रहा हूं कि मथुरा रिफाइनरी कब से शुरू होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न नहीं है।

श्री मलिक एम० एम० ए० खान : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कांडला पोर्ट में आयल के अनलोडिंग का एडीक्वेट अरेन्जमेंट न होने की वजह से क्या यह सही है कि भारी तादाद में डैमरेज देना पड़ता है ? अभी हाल ही में कई आयल टैकर ऐसे आये है, जो वहां एडीक्वेट अरेन्जमैंट न होने की वजह से पोर्ट में बाहर खड़े रहे और आपने बड़ी भारी तादाद में डेमरेज दिया है । मैं जानना चाहता हूं कि यदि डैमरेज दिया है तो कितना दिया है और कितने दिन तक टैकर खड़े रखे गये और कितना डैमरेज रोज देना पडता है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : दोनों आयल जैट्टी की कैपेसिटी क्या है और 1978-79 से हर साल कितना काम हैंडिल कर रहे हैं, उसके पूरे फिगर्स मैंने आपके सामने रखे है , यह सही है कि कभी-कभी एकदम 8, 10 आयल टैकर एक साथ आ जाते है तो वहां पर एट-ए-टाइम दो टैकर्स को बर्थ दे सकते है। उस समय अगर 7,8,9,10 आते हैं तो उनको बाहर ठहराना पड़ता है । ऐसे हालात जुलाई, 1980 से शुरू हुए हैं, अब हमारा बैटिंग पीरियड टैकर्स का 18 दिन का है । जो वैसल 6 अगस्त, 1981 को आई थी, अभी तक उसको हम बर्थ नहीं दे सके हैं । लेकिन उससे पहले जितनी भी वैसल्ज आई थी, उन सबको बर्थ दे दिया गया है । लेकिन बैटिंग पीरियड बहुत जल्दी खत्म हो जायेगा । अगर एक वक्त पर ज्यादा वेसल्ज आती है, तो उनको चन्द दिनों के लिए रुकना पडता है ।

श्री मलिक एम० एम० ए० खां : अध्यक्ष महोदय, मेरे सवाल का जवाब नही आया है । मैंने पूछा है कि जो

6 अगस्त वाले शिप खड़े हुए हैं, उनके लिए अभी तक गवर्नमेंट कितना डेमरेज दे चुकी है ।

अध्यक्ष महोदय : ये आंकड़े इस इस वक्त उनके पास नहीं होंगे । बाद मे बता देंगे ।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : इस वक्त डेमरेज की इनफरमेशन मेरे पास नहीं है । बाद में बता दूंगा ।

Big Power Rivalry in Indian Ocean

*68. PROF. MADHU DANDAVATE:
SHRI CHITTA MAHATA:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is true that the Prime Minister while, speaking at Kuwait in May, 1981, expressed concern over the growing big power rivalry in the Indian Ocean and further remarked that the confrontation in which each super power tried to establish its presence threatened us all· and

(b) if so, what steps are proposed to ensure that Indian Ocean is freed from the super power rivalry and is maintained as a zone of peace?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI P. V. NARASIMHA RAO): (a) Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi visited the State of Kuwait between May 9—11, 1981. At the end of the official visit a Joint Communique was issued which inter-alia states:—

"His Highness the Crown Prince and and Prime Minister of Kuwait and the Prime Minister of India expressed their grave concern over the increasing escalation of great power presence in the Indian Ocean area against the declared wishes of the littoral and hinterland states of the Indian Ocean. They called on the great powers to progressively reduce and eventually eliminate their military presence from the Indian Ocean. The two sides reaffirmed the need to redouble efforts for the speedy implementation of the declaration of the Indian Ocean as a Zone of Peace as contained in the 1971 United Nations General Assembly resolution on the subject The two sides affirmed their conviction that safeguarding and maintenance of peace and security in the Gulf region is the responsibility of its states alone without any foreign interference".

(b) Government of India have consistently opposed Great Power military presence in the Indian Ocean area, in bilateral contacts as also at various international and multilateral fora like the UN and Non-Aligned meetings. India is working with other Non-Aligned as also with the littoral and hinterland States to preserve the concept contained in the U.N. Declaration of 1971 which envisages the "elimination from the Indian Ocean all bases, military installations, logistical supply facilities, the disposition of unclear weapons and weapons of mass destruction and any manifestation of Great Power military presence in the Indian Ocean conceived in the Context of Great Power rivalry". The Non-aligned Foreign Ministers' Conference in New Delhi, in February, 1981, reiterated that the Indian Ocean should be free of Great Power military presence and reaffirmed their determination to work for the success of the conference on the Indian Ocean scheduled to be held in Sri Lanka in 1981. Although the prospects of convening this conference have receded it will be the endeavour of the Government of India to bring about a satisfactory implementation of the UN Declaration with the cooperation of like-minded States

PROF. MADHU DANDAVATE: Since only half a minute is left, I will ask both the supplementaries together.

The hon. Minister has, in an intelligent way, avoided answering my first question, particularly part (a) of the question, in which I have not asked as to what is the position India